

परिसीमन और लोकसभा सीटों का विस्तार क्या दक्षिण भारत के साथ अन्याय ?



सैयद जाफर हुसैन

देश में लोकसभा सीटों के विस्तार और परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर शुरू हुई बहस अब गंभीर राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दा बनती जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव उठाए गए सवाल केवल एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सामूहिक चिंता को दर्शाते हैं। प्रस्ताव है कि लोकसभा की सीटों को

943 से बढ़ाकर लगभग 100 तक किया जाए और इनका वितरण जनसंख्या (प्र. रा.) के आधार पर हो। पहली नजर में यह लोकतांत्रिक सिद्धांत "एक व्यक्ति, एक वोट" के अनुरूप लगता है, लेकिन भारत जैसे विविधताओं से भरे संघीय ढांचे में यह फार्मूला कई गंभीर असंतुलन पैदा कर सकता है।

दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पिछले कई दशकों में जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन राज्यों ने केंद्र की नीतियों का पालन करते हुए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया। लेकिन अब यदि सीटों का बंटवारा केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो इन राज्यों की संसद में प्रतिनिधित्व घट जाएगा।

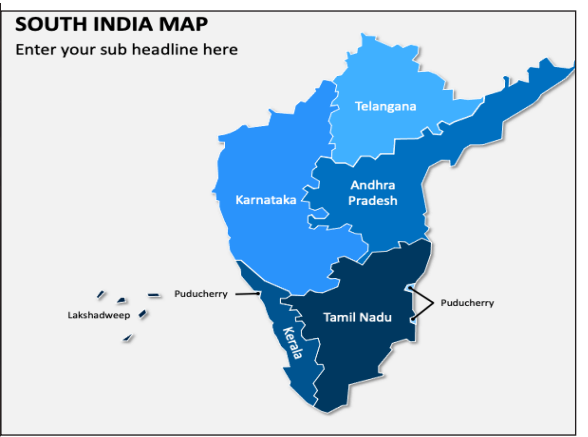
इसके विपरीत, जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है, उन्हें अधिक सीटें मिलेंगी, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत और बढ़ेगी। यह स्थिति एक तरह से "अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सजा

और कमजोर प्रदर्शन करने वालों को इनाम" देने जैसी होगी।

इतिहास इस बात का गवाह है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिए गए। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय एकता और संतुलन को बनाए रखने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को कई वर्षों तक स्थगित रखा था। उनका यह कदम दूरदर्शिता का उदाहरण था।

आज जब देश "विकसित भारत" की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहा है, तो यह आवश्यक है कि सभी क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाए। केवल जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तय करना, आर्थिक योगदान, मानव विकास और प्रशासनिक दक्षता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज करना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है कि वह इस मुद्दे पर सभी राज्यों और राजनीतिक दलों के साथ व्यापक वार्ता करे। बिना सहमति के लिया गया कोई भी निर्णय क्षेत्रीय असंतोष को जन्म दे सकता



है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक होगा।

इस संदर्भ में "हाइब्रिड मॉडल" एक संतुलित समाधान के रूप में सामने आता है। इसमें सीटों के एक हिस्से को जनसंख्या के आधार पर और दूसरे हिस्से को राज्यों के आर्थिक योगदान (जीएचपी) और विकास के मानकों के आधार पर बांटा जा सकता है। इससे न केवल प्रतिनिधित्व में संतुलन बना रहेगा बल्कि राज्यों को

बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।

साथ ही, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जैसे मुद्दों को परिसीमन और सीटों के विस्तार से अलग रखकर तुरंत लागू किया जाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र में समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

अंततः, यह केवल सीटों की संख्या का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे, क्षेत्रीय संतुलन और राष्ट्रीय एकता का

प्रश्न है। यदि इस पर संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के साथ निर्णय नहीं लिया गया, तो यह उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक खाई को और गहरा कर सकता है। भारत की असली ताकत उसकी "एकता में विविधता" है। इसलिए जरूरी है कि कोई भी निर्णय ऐसा हो जो सभी राज्यों के लिए न्यायपूर्ण, संतुलित और स्वीकार्य हो सके।



"वादे सादिक 4" की 80वीं लहर के तहत इजराइल के खिलाफ नए सैन्य हमलों की शुरुआत की गई है।

सेना के जनसंपर्क विभाग के अनुसार, इस कार्रवाई में उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में स्थित महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को भारी मिसाइल हमलों के जरिए निशाना बनाया गया। इस हमले को "या शदीद अल-कुवा" कोड नाम दिया गया और इसे लेबनान की प्रतिरोधी संगठन म्हाइवससी और दक्षिणी लेबनान के लोगों के समर्थन में बताया गया। बयान के मुताबिक, सफ़द शहर के पास स्थित इजराइली सेना के एक अहम कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया, जहां से उत्तरी सीमाओं पर सैन्य गतिविधियों की निगरानी की जाती है। सेना ने कहा कि यह कार्रवाई आने वाले लगातार हमलों की शुरुआत है, जिसमें उत्तरी फिलिस्तीन और गाजा के आसपास मौजूद इजराइली सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया जाएगा।

सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से ईरान युद्ध जारी रखने की पैरवी की: रिपोर्ट



सऊदी अरब के डेवीउउमक इपद'स. उंद निजी तौर पर क्वदंसक ज्तनउच से आग्रह कर रहे हैं कि अमेरिकी-इजराइली सैन्य अभियान को ईरान के खिलाफ जारी रखा जाए। उन्होंने इस संघर्ष को पश्चिम एशिया को नया आकार देने का "ऐतिहासिक अवसर" बताया, जबकि यह युद्ध उनके अपने

देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार। पिछले सप्ताह में कई बातचीतों के दौरान, सऊदी अरब के वास्तविक शासक मोहम्मद बिन सलमान ने किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई को कम करने के सुझाव का विरोध किया,

1। अमेरिकी अधिकारियों से जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार खाड़ी क्षेत्र के लिए स्थायी खतरा है, जिसे केवल कूटनीति से नहीं संभाला जा सकता बल्कि केवल शासन परिवर्तन के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने और भी आगे बढ़कर अमेरिकी जमीनी ऑपरेशन ईरान के अंदर करने और झीतह प्संदक को सैन्य रूप से कब्जा करने की पैरवी की, जो ईरान के अधिकांश तेल निर्यात का केंद्र है।

सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में वदंसक ज्तनउच ने ऐसे अभियान पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है, जिसमें हवाई सेना की इकाइयाँ या मरीन एम्फीबियस हमला शामिल हो सकता है।



BJP ने AIMIM विधायकों के खिलाफ राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर कार्रवाई की मांग की

श्लोकमंतंरक: तेलंगाना भाजपा ने रा. ज्यपाल"पअ व्जंज"नासं से आग्रह किया है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दें कि वे सभी इंडिया मजलिस-ए-इत्ते. हादुल मुसलमीन (IPL) के विधायकों की सदस्यता निलंबित करें, जिन्होंने विधानसभा में राष्ट्रीय गीत के प्रति अपमानजनक व्यवहार दिखाया।

भाजपा के राज्य अध्यक्ष छ त्त्तबीदकमत त्व के नेतृत्व में बुधवार, 25 मार्च को भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने

लोक मवन में राज्यपाल से मुलाकात की और IPL विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाला ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने राज्यपाल का ध्यान इस ओर दिलाया कि 16 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन, जब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में 150 वर्षों की वर्षगांठ पर राष्ट्रीय गीत घोषित किए गए "वंदे मातरम" का पाठ किया जा रहा था, IPL के सदस्य सदन से बाहर चले गए।

SADA-E-HUSSAINI

INFORMATION DESK

STAY CONNECTED. STAY INFORMED.

If you have any news, announcements, community updates, or Islamic event details you would like to share, Sada-e-Hussaini is here to help spread the word.

Whether it's a Majlis, Juloos, Niyaz, religious program, or any important update related to the minorities community, we're just a message away.

CONTACT US TODAY!

9490618051
8019162110